Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2020 SHISRRJ | Volume 3 | Issue 2 | ISSN : 2581- 6306

ग्रामीण भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति

डॉ0 राजन गुप्ता
समाजशास्त्र विभाग
माँ गायत्री महाविद्यालय
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश : शिक्षा प्रत्येक युग में सभ्य मानव के जीवन का एक अपरिहार्य अंग रहा है। वर्तमान युग की यह एक बहुत बड़ी मांग है कि समाज शिक्षा के लिये सभी साधनों को प्रदान करें और शिक्षा समाज के अनुरूप हो यदि हम शिक्षा की गहराई में दृष्टिपात करें तो यह ज्ञात होता है कि शिक्षा का सर्वोच्च कार्य, व्यक्ति एवं समाज के आचरण को विकसित करना है। वर्तमान सरकार ने देशभर में मूलभूत ढांचागत सुधारों और विस्तार कार्यक्रमों को तेजी से बढ़ावा दिया है, जिससे ग्रामीण विद्यालयी ढांचे में भी पर्याप्त सुधार होने की संभावना है। दावों को सच माने तो लगभग सभी ग्रामीण विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के लिये अलग–अलग शौचालय उपलब्ध हो गया हैं, बिजली पहुंच गई हैं। विद्यालयों तक पक्की सड़के पहुँच गयी है; लेकिन शिक्षकों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटरों, शिक्षण सहायक युक्तियों विद्यालय की उपयुक्त पक्की इमारतों आदि का अभाव बना हुआ है; और इसके बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण–अधिगम वातावरण का निर्माण नहीं हो सकता। प्रस्तुत शोध ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना है।

मुख्य शब्द : व्यक्ति एवं समाज, मूलभूत ढांचा, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला आदि।

वर्तमान सामाजिक–सांस्कृतिक परिदृश्य में मानव संसाधनों का समुचित विकास भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। औद्योगिक क्रांति के साथ ही भारत सहित विश्व के समस्त देशों में शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के एक प्रमुख वाहक के रूप में देखा जाने लगा है।[1] अब विकसित तथा विकासशील सभी देशों में शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य और नीति की व्याख्या और रचना आधुनिक और उत्तर आधुनिक वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखकर की जाने लगी है।

वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल 645481 गांव हैं। देश की आबादी का 67 प्रतिशत अभी गांवों में रहता है।[2] हम जानते हैं कि शिक्षा राष्ट्र की प्रगति का आधार है कि उचित शिक्षा की व्यवस्था किए बिना कोई राष्ट्र विश्व का अग्रणी राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए यह देखना समीचीन होगा कि वर्तमान में ग्रामीण भारत में शिक्षा व्यवस्था किस अवस्था में है। जनवरी से जून 2014 के बीच 4577 गांवों में 36479 परिवारों से संपर्क कर

किए गए 71वें क्रम के राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण के अनुसार 7 वर्ष से अधिक से पुरुषों में साक्षरता दर 83 प्रतिशत और महिलाओं में 67 प्रतिशत पाई गई जबकि यहां स्नातक अथवा उच्च स्तर के पुरुष्ज्ञ 4.5 प्रतिशत तथा महिलाएँ 2.9 प्रतिशत पाई गई।

8वें अखिल भारतीय विद्यालयी शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6.75 लाख प्राथमिक, 3.04 लाख उच्चतर प्राथमिक, 82.8 हजार माध्यमिक, 36.9 हजार उच्चतर माध्यमिक तथा 1.18 हजर डिग्री कॉलेज कार्यरत है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक गांव के लिए एक प्राथमिक विद्यालय एक किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है और उपयुक्त प्रबंधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जा सकती है।

ग्रामीण शिक्षा की वर्तमान स्थिति :

वर्तमान सरकार ने देशभर में मूलभूत ढांचागत सुधारों और विस्तार कार्यक्रमों को तेजी से बढ़ावा दिया है, जिससे उपर्युक्त ग्रामीण विद्यालयी ढांचे में भी पर्याप्त सुधार होने की संभावना है। दावों को सच मानें तो लगभग सभी ग्रामीण विद्यालयों में बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय उपलब्ध हो गए हैं, बिजली पहुंच गई है। विद्यालयों तक पक्की सड़कें पहुँच गई है लेकिन शिक्षकों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटरों, शिक्षण सहायक युक्तियों, विद्यालय की उपयुक्त पक्की इमारतों आदि का अभाव बना हुआ है और इसके बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण–अधिगम वातावरण का निर्माण नहीं हो सकता है।[3] इसलिए उपर्युक्त सभी मुद्दों पर तेजी से काम करने की आवश्यकता है।

परिलक्षित हो रहे परिवर्तन :

ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई दे रहे सार्थक बदलाव शिक्षा के अधिकार कानून के धरातल पर क्रियान्वित होने के परिणाम है। यही वजह है कि लगभग सभी सरकारी स्कूलों में नामांकन की वृद्धि दर्ज की गई है। शिक्षा का अधिकार कानून – 2009 के बाद स्कूलों की संख्या में वृद्धि, शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, शौचालय और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार और स्कूल तक बच्चों को लाने के लिये की जाने वाली पहलों की वजह से सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है।

लेकिन एक–चौथाई सरकारी स्कूलों में आज भी बच्चों का नामांकन प्रतिशत 60 और इससे कम है। इसमें वे बच्चे शामिल हैं जो निःशुक्ल और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार न मिलने पर स्कूल नहीं जा पाते हैं, और जो शिक्षा के बदले घरेलू व खेती के कामों में बड़ों का हाथ बटाते हैं।

ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ :

- आज भी ऐसे ग्रामीण स्कूल है, जहाँ कमरों व डेस्क–बेंच जैसी मूलभूत सुविधाएँ पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है।
- बहुत से स्कूलों में बच्चे बरामदों व पेड़ों के नीचे बैठकर ही पढ़ते नजर आते हैं
- शौचालय स्कूलों में है परन्तु पानी के अभाव में साफ–सफाई रख पाना मुश्किल हो जाता है।
- ग्रामीण स्कूलों में मिड–डे मिल संचालन के तौर–तरीकों पर भी सवाल उठाए जाते हैं। स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाने में ही शिक्षकों का काफी समय व्यर्थ हो जाता है। अधिकारिक स्तर पर मिड–डे मील स्कीम के कार्यान्वयन को लेकर ठोस योजना का अभाव एक बड़ा गतिरोध है।

- देश के बहुत से ग्रामीण स्कूल ऐसे है जहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से एड्सेट के उपकरण लगाए गए हैं। लेकिन भारी–भरकर खर्च से लगाए गए ये उपकरण अधिकांश स्कूलों में मात्र शो–पीस बनकर रह गए है।
- ग्रामीण सरकारी स्कूलों की छवि गरीबों और अशिक्षितों के बच्चों में स्कूल वाली बन गई है, जो पूरी तरह शिक्षकों की दया पर निर्भर है।
- आज भी शिक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों में अध्यापकों के वेतन और प्रशासन पर ही खर्च होता है। फिर भी विश्व में बिना अनुमति अवकाश लेने वाले अध्यापकों की संख्या भारत में सबसे अधिक है।
- ग्रामीण स्कूलों में अक्सर यह देखने में आता है कि अध्यापक आते ही नहीं है और चार में से एक सरकारी स्कूल में रोज कोई–न–कोई अध्यापक छुट्टी पर होता है।[4]

संविधान में हिंसा को समवर्ती सूची में रखा गया है और इसका प्रमुख जिम्मा राज्यों पर है। ऐसे में जरूरत है कि सभी राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार इसकी चुनौतियों को अपने ढंग से हल करें। ऐसा हुआ भी है और इसके अलग–अलग परिणाम सामने आए। जिन राज्यों में स्कूली शिक्षा का विकास बेहतर तरीके से हुआ, वहाँ गरीब वर्षों की शिक्षा संबंधी चुनौतियों को प्राथमिकता दी गई। लेकिन आज भी स्थिति यह है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने के लिये निजी स्कूलों में भेजता है।

शिक्षा के सहायक उपक्रम :

ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने और भी कई तरह के ढांचागत व्यवस्था करने के लिए कई नायाब कदम उठाए है यथा–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए इन पूर्णतः आवासीय सहशिक्षा विद्यालयों की प्रस्तावना की थी, जो छठी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करते हैं। 1986 में प्रायोगिक स्तर पर मात्र दो स्कूलों से शुरू किए गए प्रयोग के अंतर्गत आज 598 स्कूल चल रहे हैं जिनमें 34 राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के 1.93 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उच्चस्तरीय शिक्षा व्यवस्था की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।[5]
- प्राथमिक से लकर विश्वविद्यालयी स्तर और कुछ हद तक व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराने के लिए देश में शिक्षा संस्थानों में जाकर पड़ पाने में असमर्थ बच्चों के लिए कोरेस्पोंडेंस कोर्स, मुक्त विद्यालय, ऑनलाइन शिक्षा तथा दूसरा शिक्षा संस्थानों जैसी पहल शुरू हुई तो इनका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार में भी हुआ।
- 10 जून 2017 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 32 चैनलों वाले स्वयं प्रभा समूह का उद्घाटन किया गया। इन चैनलों को डीटूएच के माध्यम से देश में किसी भी जगह देखा जा सकता है।
- भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 के लिये नई स्वीकृत शिक्षा योजना बनाई है। इस योजना में सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित है।

इसका उद्देश्य सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा पूरे देश में प्री नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा सुविधा को उपलब्ध करने के लिये राज्यों की मदद करना है। इसके प्रमुख लाभ अद्योलिखित हैं। यथा–

- शिक्षा के संदर्भ में समग्र दृष्टिकोण।
- पहली बार स्कूली शिक्षा के लिये उच्चतर माध्यमिक और नर्सरी स्तर की शिक्षा का समावेश।
- संपूर्ण इकाई के रूप में स्कूलों का एकीकृत प्रबंधन।
- गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर ध्यान, सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने पर जोर।
- शिक्षकों के क्षमता विकास को बढ़ाना।
- शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिये प्रशिक्षण संस्थाओं को सशकृत बनाना।
- डिजिटर बोर्ड और स्मार्ट क्लासरूम के जरिये शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिक के इस्तेमाल को बढ़ाया देना।
- विद्यालयों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए स्वच्छता गतिविधियों की विशेष व्यवस्था।
- सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुधारना।[6]

उक्त योजनाओं के बावजूद अभी भी जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की पहुंच बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक गति दी जाए और यहाँ शिक्षा के आधारभूत ढांचे को सशक्त किया जाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. बघेल, डी0ए0, भारत में सामाजिक परिवर्तन, म0प्र0, पृ0 30
2. एस0के0ओझा, जनसंख्या एवं नगरीकरण, इलाहाबाद, पृ0 15
3. कुरूक्षेत्र, मासिक पत्रिका, भारत सरकार, मार्च 2018, पृ0 25
4. योजना, पत्रिका, भारत सरकार 2017 (फरवरी), पृ0 10
5. www.wikipedia.com
6. एजुकेशनल स्टेटिस्टिकल इन ग्लॉस, 2016, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।